आपका पक्ष

चीनी मिलों से खाद्य प्रसंस्करण का कार्य

उत्तर प्रदेश सरकार चीनी मिलों से खाद्य प्रसंस्करण का कार्य लेने की योजना पर विचार कर रही है। अगर यह योजना सफल हो जाती है तो चीनी मिलों तथा किसानों का काफी हद तक लाभ हो सकता है। चीनी मिलें संयंत्र एक वर्ष में करीब छह महीने ही चलती हैं। गन्ना सीजन खत्म होते ही मिलें बंद हो जाती हैं। इस अवधि में संयंत्र के परिसर में अन्य कार्य किए जा सकते हैं। अगर चीनी मिलों में खाद्य प्रसंस्करण की मशीनें लगा दी जाए तो खाद्य पदार्थों को प्रसंस्कृत किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश में उपज की अधिकता के कारण भी नुकसान उठाना पड़ता है। हाल में आलू की अधिक उपज के कारण किसान सड़कों पर आलू फेंकने को मजबूर थे। अगर आलू प्रसंस्कृत किया जाता तो इससे किसानों को दोगुना लाभ हो सकता था। अगर चीनी मिलों एक निश्चित अवधि

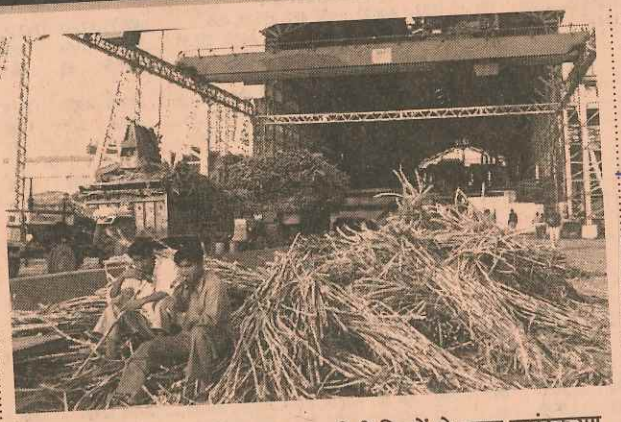

के लिए खाद्य प्रसंस्करण संयंत्र में बदल दिया जाए तो कई समस्याओं का हल निकल आएगा। वर्तमान में भंडारण की कमी की वजह से चीनी के दाम भी काफी गिर गए हैं। अगर उचित भंडारण की व्यवस्था कर दी जाए तो खाद्य पदार्थों का उचित मूल्य मिल सकता है। सरकार को राज्य में कोल्ड स्टोरेज की संख्या में बढ़ोतरी के साथ इसके उचित प्रबंधन पर भी जोर देना चाहिए। इससे प्रदेश में रोजगार के अवसरों का भी सृजन होगा। प्रदेश में फसल की बुआई से लेकर कटाई, भंडारण तथा प्रसंस्करण और बिक्री के लिए उचित बाजार की व्यवस्था किए जाने की जरूरत है।

कृष्णा शर्मा, इलाहाबाद

चीनी मिलों से खाद्य प्रसंस्करण का कार्य लेने से किसान सहित कई लोगों को फायदा होगा

Business Standard
27/4/18